



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134]
No. 134]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15, 1984/भाद्र 24, 1906

NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 15, 1984/BHADRA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1984

सावजनिक सूचना सं० 24-ईटीसी (पीएम)/84

विषय : 1-1-1985 से 31-12-1985 तक संयुक्त राज्य
अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों,
कनाडा, आस्ट्रिया और स्वीडन को खुले सामान्य
लाइसेंस-3 के अन्तर्गत मूल के कुछ कपड़ों और/या
ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार मर्दों के
निर्यात के लिये योजना।

1. योजना

मि० सं० 2/27-ए/84-ई-I :—यह योजना 1-1-85 से
31-12-85 तक की अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमरीका,
यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय
गणराज्य, फ्रांस, इटली, बेनिनक्स, यू०के०, आयरलैंड, डेनमार्क
और ग्रीस), आस्ट्रिया कनाडा और स्वीडन को सूत, ऊन, और
मनुष्य निर्मित धागों के कुछ कपड़ों और/या तैयार मर्दों के
निर्यात से संबंधित है।

2. योजना के प्रशासन के लिए अधिकरण

(1) जब तक अन्यथा रूप से निवेश न किये जायें,
सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (टैक्सप्रोसिल) सभी वस्त्रों
और तैयार वस्तुओं के लिए निर्यात हकदारी का आबंटन
करेगी किन्तु ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुओं को छोड़कर
जिनकी निर्यात हकदारी का आबंटन ऊन तथा ऊनी वस्त्र
निर्यात संवर्धन परिषद् (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी) द्वारा किया
जायेगा। लेकिन सभी वस्त्र और तैयार वस्तुएं जिनमें ऊनी
वस्त्र और तैयार वस्तुएं भी शामिल हैं के लिए आवश्यक
प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जायेगा।
योजना के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की
सूची सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् और ऊन तथा ऊनी
वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध है। सरकार
को यह अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे, इस योजना
के प्रशासन के लिये अधिकरणों के संबंध में परिवर्तन कर
सकती है।

(2) निर्यात हकदारी का आबंटन केवल सक्षम पंजीकरण
प्राधिकारियों के पास पंजीकृत निर्यातकों को ही किया जाएगा।

3. मात्रा आबंटन की प्रक्रिया और आबंटन वर्ष का विभाजन

निर्यात के लिये मात्रा के आबंटन की तीन पद्धतियाँ होंगी :—

- (1) वार्षिक स्तर के 40% का आबंटन भूतकालीन निष्पादन के आधार पर किया जायेगा और 40% का पहले आये सो पहले पाये संविदा आरक्षण के आधार पर और 20% पहले आये सो पहले पाये तैयार वस्त्र के आधार पर।
- (2) भूतकालीन निष्पादन पद्धति के मामले में 1-1-1985 से 30-9-1985 तक की एक एकल आबंटन अवधि होगी। पहले आये सो पहले पाये संविदा आरक्षण पद्धति और पहले आये सो पहले पाये तैयार वस्त्र पद्धति के मामले में वर्ष का विभाजन दो छमाही अवधियों अर्थात् 1-1-1985 से 30-6-1985 और 1-7-1985 से 31-12-85 में किया जायेगा।
- (3) पहले आये सो पहले पाये संविदा आरक्षण पद्धति और पहले आये सो पहले पाये तैयार माल पद्धति के अधीन उपलब्ध मात्रा का 60% प्रथम अवधि जनवरी/जून 1985 के दौरान लदान के लिये आबंटित किया जायेगा और 40% की दूसरी अवधि जुलाई/दिसम्बर 1985 के दौरान लदान के लिये आबंटित किया जायेगा। लेकिन उपर्युक्त अवधियों/पद्धतियों वार अनुपातों की मांग की प्रवृत्ति और अन्य पैरामेटर्स के आधार पर सरकार द्वारा आशोधित किया जा सकता है।

4. खण्ड के लिये आरक्षण

अहाँ पर सूती, ऊनी और मनुष्य निर्मित धागे की निर्यात हकदारी मिश्रित की जाती है, ऊनी और संश्लिष्ट सामानों के लिये आरक्षण विशेष मात्राओं की शर्तों के अनुसार किया जायेगा। वस्त्र आयुक्त द्वारा वास्तविक मात्राओं का निश्चय गत वर्ष के पैटर्न और चालू वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः परिषदों से पक्की जरूरतें प्राप्त करने के बाद किया जायेगा।

5. भूतकालीन निष्पादन हकदारी योजना

5(1) हकदारियों का निश्चय करने के लिये एजेन्सी प्रत्येक निर्यातक के संबंध में भूतकालीन निष्पादन योजना के अधीन हकदारी की गणना करने के लिये एजेंसी सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई (टैक्सप्रोसिल) होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रिया विधियाँ निर्धारित करेंगे और टैक्सप्रोसिल के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

5(2) निर्धारित अवधि और उच्चतम सीमा

हकदारी का निश्चय प्रत्येक निर्यातक के लिये 1980, 1981, 1982, 1983 और जनवरी/जून, 1984 के दौरान किये गये निर्यातों के औसत के आधार पर प्रत्येक

देश/श्रेणी समूह के लिये यथा अनुपात किया जायेगा। आबंटन यथानुपात के आधार पर किया जायेगा। लेकिन कोई भी निर्यातक प्रत्येक श्रेणी/देश में आधार अवधि में अपने वार्षिक औसत निर्यात से अधिक के लिये हकदार होगा।

5(3) निष्पादन बाण्ड

भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिये मात्रा प्राप्त करने वाले निर्यातकों को निष्पादन बाण्ड भरे बिना ही 31-3-1985 तक अपनी हकदारी का उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी।

5(4) निर्यातकों को यह विकल्प दिया जायेगा कि वे 31-3-1985 तक अप्रयुक्त हकदारियों को अभ्यर्पित कर दें या उन्हें ऐसी मात्रा रखने की अनुमति दी जायेगी जो वे 31 मार्च, 1985 से पहले या इस तिथि को 50 पैस प्रति किलो ग्राम की दर पर बैंक गारन्टी या नकद निक्षेप द्वारा समर्थित निष्पादन बाण्ड देकर रखने की इच्छा करें और जिन मामलों में यूनिट का आबंटन किलो ग्रामों में हो वहाँ यह दर ई ई सी देशों को हमालों के लिये 12 पैसे प्रति दर्जन, संयुक्त राज्य अमरीका को टेरि तोलियों के लिये 24 पैसे प्रति दर्जन और कनाडा को ऊनी बर्मिटिड वस्त्रों के लिये 5 पैसे प्रति बर्ग गज होगी।

5(5) निर्यातकों को ऐसी मात्रा और भी रखने का विकल्प दिया जायेगा जो मात्रा वे 30 सितम्बर तक पोतलदान के लिये रखने की इच्छा करें। यह विकल्प उपर्युक्त पैरा 5(4) में निर्दिष्ट दरों से दोगुनी बैंक गारन्टी या नकद निक्षेप द्वारा समर्थित निष्पादन बाण्ड 30-6-1985 से पहले या इस तिथि को प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

5(6) यदि उपयोग 30 सितम्बर, 1985 से पहले 75% से कम रहता है तो निर्यातक को पैरा 5(5) में निर्दिष्ट दूर से दुगुने दर पर निष्पादन बाण्ड के निष्पादन द्वारा 31 दिसम्बर, 1985 तक पोतलदान करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिये विकल्प दिया जायेगा।

5(7) हस्तान्तरण

(क) 30-9-1985 तक किसी भी समय किसी भी निर्यातक को अपनी हकदारी में किसी भी हिस्से का हस्तान्तरण करने का एक निर्यातक को विकल्प होगा।

(ख) हस्तान्तरित मात्रा उस हस्तान्तरी के निर्यात के रूप में मानी जाएगी जो वास्तव में माल का लदान करता है।

(ग) हस्तान्तरी के पास की हकदारी उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी जो हस्तान्तरक के पास हकदारी के लिए लागू हैं।

(घ) एक निर्यातक जो पूर्ण रूप या आंशिक रूप से किसी विशेष देश/क्षेत्री में किसी अन्य निर्यातक से हस्तान्तरण द्वारा हकदारी प्राप्त करता है तो वह उसी देश/क्षेत्री में किसी अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी को हस्तान्तरित करने का हकदार नहीं होगा।

(ङ) विशेष/देश/क्षेत्री के भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण उस निर्यातक के लिये अनुमय नहीं होगा जिसके पास उसी देश/क्षेत्री में "पहले आए, सो पहले पाए" संविदा आरक्षण कोटा हो।

6. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर संविदा आरक्षण पद्धति

6.(1) पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण आधार पर आबंटन के लिये, निर्यातक को आवेदन पत्र के साथ यदि आबंटन कि० ग्रा० में है तो 1/- रुपया प्रति कि० ग्रा० की दर पर यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों के लिए स्मालों के लिए 12 पैसे प्रति दर्जन, यू० एम० ए० के लिये तौलियों के लिए 24 पैसे प्रति दर्जन और कनाडा के लिये ऊनी वेसिटिड वस्त्रों के लिये 5 पैसे प्रति बर्ग मीटर की दर पर परिकलित बैंक गारंटी द्वारा समर्पित निष्पादन बांड प्रस्तुत करना पड़ेगा।

6.(2) उपर्युक्त कंडिका 6(1) में विनिर्दिष्ट दुगुनी दरों पर निष्पादन बाण्ड भेज कर निर्यातक अपने आबंटन अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि उसने 30 जून 1985 तक अपनी हकदारी का 75% हिस्सा उपयोग कर लिया है।

6.(3) यदि किसी निश्चित दिन किसी देश/क्षेत्री में वितरण के लिए आवेदित कुल मात्रा उपलब्ध मात्रा से अधिक है तो आबंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जायेगा।

7. पहले आए सो पहले पाए तैयार माल पद्धति

7(1) पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर मात्रा के आबंटन के मामले में निर्यातक के आवेदन पत्र के साथ पोतलदान बिल, वस्त्र समिति निरीक्षण, प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो ए आर 4/ए आर 5-प्रपत्र और 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० की दर पर परिकलित अजित धन निक्षेप के लिये चेक प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वास्तविक पोतलदान प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जब्त कर लिया जायेगा।

7(2) यदि किसी विशेष दिन आवेदित कुल मात्रा किसी देश/क्षेत्री में वितरण के लिये उपलब्ध मात्रा से कम है तो आबंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जायेगा।

8. प्रमाणीकरण/पोतलदान

आबंटन की सभी तीनों पद्धतियों के अन्तर्गत टेक्सोप्रासिल द्वारा प्रमाणीकरण किसी भी मामले में प्रमाणीकरण की

तारीख से 21 पूरे दिन की अवधि के लिए पोतलदान के लिए इस शर्त के अधीन होगा कि कोई भी प्रमाण-पत्र 31 दिसम्बर, के बाद वैध नहीं होगा।

9. धीमी रफ्तार की मर्दे

वस्त्र आयुक्त भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान पद्धति के आधार पर धीमी रफ्तार वाली मर्दों का अभिज्ञान करेगा और उनकी सूची को घोषणा करेगा। ऐसी मर्दे निम्नलिखित रियायतों के लिए पात्र होगी :—

(क) निष्पादन गारंटी के मुद्दे सुरक्षा से संबंधित प्रावधान उन मन्द गति वाली मर्दों के मामले में जो कि इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिज्ञात हैं, भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग कर दी जाएगी।

(ख) मन्द गति वाली मर्दों की पहचान के लिए, आवेदक की बैंक गारंटी अथवा नकद निक्षेप के बिना वस्त्र संवर्धन समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में केवल निष्पादन बाण्ड ही भेजा जाएगा।

10. पेशगी धनराशि का निक्षेप बैंक गारंटी और उनकी जब्ती

10(1) जो निर्यातक पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण अथवा पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के अन्तर्गत विशेष निर्यात हकदारी अथवा पूरे वर्ष भूतकालीन निष्पादन के अन्तर्गत उसे आबंटित हकदारी कोटे के 90% तक निष्पादन करता है तो उसे जुमनि का भुगतान नहीं करना होगा। जो निर्यातक 75% तक किन्तु 90% से कम निर्यात करता है, उसे भी अनुपात के हिस्सा में जुमनि देना होगा। यदि निर्यात हकदारी का उपयोग 75% से कम है तो निर्यातक पूरे पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जब्त कराने के लिए उत्तरदायी होगा। जब भी ऐसा होगा, यह अनिवार्य श्राद्धता के अधीन लागू होंगे।

10(2) भूतकालीन निष्पादन हकदारी के मामलों में 1-7-1985 तक रखी गई मात्रा में से बची हुई मात्रा का उपयोग 30 सितम्बर तक करना होगा। 1-7-85 के बाद पैरा 5 (6) के विवरण के अनुसार प्रतिभूति देय होगी।

10(3) समय-वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध अवधि के एक भाग के भीतर दाखिल कर दिए जाएंगे।

10(4) इस नीति के अनुसार जिन निर्यातकों को निर्यात या आबंटन किया गया है किन्तु जो उसका उपयोग नहीं करते हैं, भविष्य में वे आबंटन के अयोग्य साबित होंगे और उन पर बिना किसी पक्षपात के उस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है।

11. पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जप्त करने के विरुद्ध अपील

आबंटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जप्त करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए केवल निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जप्त किए जाने पर संबंध निर्यातक ऐसे जप्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बंबई को उसके विरुद्ध अपील कर सकती है। वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे। यदि किसी मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग को की जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गयी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

12. निर्यात हकदारी आबंटन का पर्यवेक्षण

वस्त्र आयुक्त, बंबई निर्यात हकदारी के आबंटन से संबंधित मामले पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के अधिकार को जारी रखेगा। एक समन्वय समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे और संबंध निर्यात संबंधन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, वे समय समय पर नीति के प्रचालन की पुनरीक्षा करेंगी। विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

13. सीमाशुल्क द्वारा निकासी

(क) निर्यात के अधीन उत्पाद

पोतलदान की अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पतनों पर सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-2 माल परेक्षणों के लिए मूल पोत-परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद

जहां तक नियंत्रित मर्चों के संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं के निर्यात का संबंध है, वहां सीमाशुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कंबीनेशन प्रपत्र के भाग 2 में, निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ग) भारतीय मर्च के लिए क्रियाविधि

उन भारतीय मर्चों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परंपरागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, यू०एस०ए०, फिनलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलदान सीमाशुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय या वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर अनु-मित किया जाएगा।

14(क) निर्यात प्रमाणपत्र, उद्गम प्रमाणपत्र और बीसा संगत द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित

प्रमाण-पत्र सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य परिषद् द्वारा जारी किए जाएंगे :—

(1) ई ई सी

(क) बुने हुए पावरलूम और मिल निर्मित मूल की पोशाकें, जो नियंत्रण के अधीन हैं, के लिए निर्यात प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।

(ख) बुने हुए/पावरलूम/मिल निर्मित मूल की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, के लिए उद्गम-प्रमाणपत्र

(2) आस्ट्रिया

नियंत्रण या निगरानी की शर्त के अधीन सूती पावरलूम/मिल निर्मित पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(3) कनाडा

बुने हुए पावरलूम और मिल निर्मित मूल की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(4) यू० एस० ए०

(क) यू०एस० डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की मिल निर्मित/पावरलूम पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए बीसा।

(ख) यू०एस० डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाणपत्र।

(5) स्वीडन

सभी मिल निर्मित/पावरलूम/हैण्डलूम/बुनी हुई किरासियां से बुने हुए मात्रिक उद्गम के अधीन निर्यात प्रमाणपत्र।

14(ख) हथकरघा छूट प्रमाणपत्र

नियंत्रित मर्चों से संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं के कनाडा को निर्यात, सूती वस्त्र हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं का आस्ट्रिया को निर्यात, सभी हथकरघा वस्त्र और तैयार वस्तुओं का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राज्यों तथा यू०एस०ए० को निर्यात के मामले में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौते में यथा निश्चित प्रमाण पत्र जारी करेगा।

15. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपलब्ध का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

16. संबंध निर्यात संबंधन परिषद् और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नलिखित अनुसार हैं :—

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
न्यू सी०जी०ओ० बिल्डिंग,
न्यू मैरीन लाइन्स,
पोस्ट बॉक्स नं० 11500,
बंबई-400020।

2. सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद्,
इंजीनियरिंग सेंटर,
5वीं मंजिल,
9-मैथ्यू रोड,
बंबई-400 004.
3. सिल्क और रायन टेक्सटाइल निर्यात संबंधन परिषद्,
रेशम भवन,
बीर नारीमन रोड,
बंबई-400 020.
4. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद्,
612/714, अशांक इस्टेट, 24, बागमबाई रोड,
नई दिल्ली-110 001.
5. कारपेट निर्यात संबंधन परिषद्,
दुकान नं० बी० 115, सेक्टर-18,
पोस्ट आफिस नांयश, जिला गाजियाबाद।
6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),
वेस्ट ब्लॉक, 7, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-110 022.
7. वस्त्र समिति,
"क्रिस्टल" 79, डा० एनो बेसन्ट रोड,
बर्ली, बंबई-400 018.

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th September, 1984

PUBLIC NOTICE NO. 24 ETC (PN)84

Sub : Scheme of exports under OGL-3 of certain fabrics and/or made-up items made from cotton, Wool and man-made fibres, to USA, European Economic Community member-states (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benclux, U.K. Ireland, Denmark and Greece) Austria, Canada, and Sweden from 1-1-1985 to 31-12-1985.

1. The Scheme

F. No. 2/27-A/84-EI.—This scheme relates to the exports of certain fabrics and/or made-up items of cotton, wool and man-made fibres to USA, European Economic Community member-states (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benclux, U.K. Ireland, Denmark and Greece) Austria, Canada, and Sweden for the period 1-1-1985 to 31-12-1985.

2. Agencies for the Administration of the Scheme.

2(i) Unless otherwise directed, the Cotton Textile Export Promotion Council (TEXPROCIL) will allocate export entitlements for all fabrics and made-ups except woollen fabrics and made-ups for which export entitlement allocation will be done by the Wool and Woollen Export Promotion Council (W and WEPC). However necessary certification for all fabrics and made-ups including the woollen fabrics and made-ups will be done by the Cotton Textiles Export Promotion Council. Lists of categories of textile products covered under the scheme are available with

the Cotton Textiles Export Promotion Council and the Wool and Woollen Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes as considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the scheme.

2(ii) Export Entitlements will be allotted only to registered with the Competent Registering Authorities.

3. Systems and quantum of allotment and divisions of the allotment year.

There will be three systems of allocation of quantity for export :—

3(i) 40 per cent of the annual level will be allocated on the basis of past performance, 40 per cent on the basis of First-come first-served (FCFS) Contract Reservation and 20 per cent of FCFS Readygoods basis.

3(ii) In the case of past performance, system there will be a single period of allocation from 1-1-1985 to 30-9-1985. For FCFS Contract Reservation system and FCFS Readygoods system, the year will be divided into two six monthly periods i.e. 1-1-1985 to 30-6-1985 and 1-7-1985 to 31-12-1985.

3(iii) 60 per cent of the quantity available under the systems of FCFS Contract Reservation and FCFS Readygoods will be allocated for shipment during the first period January/June, 1985 and 40 per cent for shipment during the second period—July/December, 1985. The above periods/system-wise ratios may, however, be modified by the Government depending upon the demand patterns and other parameters.

4. Reservation for segments.—Wherever export entitlements for cotton, woollen and man-made fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic items will be done in terms of specific quantities. The actual quantities will be determined by the Textile Commissioner after ascertaining the firm requirements from the respective Councils keeping in view the past pattern and prevailing trends.

5. Past Performance Entitlement System

5(i) Agency for determining entitlements.—The Agency for calculation of the entitlement under the past performance system in respect of the each exporter will be the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL). The Textile Commissioner will lay down procedures in this regard and supervise the work of the TEXPROCIL.

5(ii) Base Period and Ceiling.—The entitlement shall be determined pro rata for each country/category combination on the basis of the average of exports during 1980, 1981, 1982, 1983 and January/June 1984 for exporter. The allotment will be made on pro rata basis. No exporter shall, however, be entitled to more than his annual average exports in the base period in each category/country.

5(iii) Performance bond : The exporters qualifying for past performance entitlement will be allowed to utilise their entitlement without executing performance bond upto 31-3-1985.

5(iv) The exporters will be given the option to surrender the unutilised entitlements by 31-3-1985 or retain such quantity as they may desire by giving performance bond backed either by Bank Guarantee or cash deposit on or before 31st March, 1985, at the rate of 50 paise per kg., where the unit of allotment is in terms of kgs., 12 paise per dozen for handkerchiefs to EEC countries, 24 paise per dozen for terry towels to USA and 5 paise per sq. yard for woollen worsted fabrics to Canada.

5(v) Exporters will be given further option to retain such quantity as they may desire for shipment upto 30th September on giving performance bond backed by Bank Guarantee or cash deposit at double the rates specified at Para 5(iv) above on or before 30-6-1985.

5(vi) Where the utilisation is not less than 75 per cent before 30th September, 1985, the exporter will be given an option to seek extension for shipment upto 31st December, 1985 by executing a performance bond at double the rates specified in paragraph 5(v).

5(vii) Transferability : Past Performance Entitlement shall be transferable subject to the following conditions:—

- (a) An exporter will have the option to transfer any portion of his entitlement to any other registered exporter at any time upto 30-9-1985.
- (b) The quantity transferred shall be counted as exports of the transferee, who actually ships the goods.
- (c) The entitlement in the hands of the transferee shall be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferer.
- (d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country/category, either in full or in part, will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country/category.
- (e) Transfer of Past Performance Entitlement in a particular country/category shall not be allowed to the exporters who have FCFS contract reservation quota in the same category/country.

6. FCFS Contract Reservation System

6(i) For allotment on FCFS Contract Reservation basis, the exporter will have to submit alongwith the application, performance bond backed by bank guarantee or by cash deposit calculated at the rate of Re. 1 per kg. where allotment is in kgs., 12 paise per dozen for handkerchiefs to EEC, 24 paise per dozen for towels to USA and 5 paise per sq. meter for woollen worsted fabrics to Canada.

6(ii) The exporter may seek extension for the next allotment period by executing performance bond at double the rates specified in para 6(i) above, provided he has utilised not less than 75 per cent of his entitlement by 30th June, 1985.

6(iii) If on any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country/category, the allotment will be made on high price basis.

7. FCFS Readygoods System

7(i) In the case of allocation of quantity on the basis of FCFS Readygoods, the exporter will have to submit alongwith the application shipping documents the Textiles Committee Inspection certificate AR4/AR5 forms wherever applicable and a cheque towards earned money deposit calculated at the rate of 50 paise per kg. which shall be forfeited if proof of actual shipment is not produced within the prescribed time limit.

7(ii) If any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country/category, the allotment will be made on high price basis.

8. Certification/shipment

Certification by TEXPROCIL under all the three systems of allotment will be valid for shipment for a period of 21 clear days from the date of certification subject to the condition that no certificate shall be valid beyond 31st December, in any case.

9. Slow moving Items.

The Textile Commissioner will identify and announce a list of slow moving items on the basis of past exports and prevailing trends. Such items will be eligible for the following relaxations:—

- (a) The provisions regarding security against performance guarantee would be dispensed with in the case of slow moving items, specially identified for this purpose, by the Textile Commissioner on the basis of past exports and prevailing trends.
- (b) For the identified slow moving items, applicants will have to submit only the performance bond in the proforma prescribed by TEXPROCIL without any Bank guarantee or cash deposit.

10. Earnest Money Deposit/Bank Guarantee and Forfeiture thereof.

10(i) An exporter, who performs not less than 90 per cent of the export entitlements allotted to him under past performance entitlement and FCFS contract reservation systems in a particular export entitlement period will not be liable to forfeiture of performance bond. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will have to pay proportionate forfeiture. If the export entitlement utilisation is less than 75 per cent the exporter will be liable to forfeiture of his performance bond in full. This will be subject to force major conditions wherever these arise.

10(ii) In the case of Past Performance Entitlement, the quantity that remains to be utilised by 30th September out of the quantity retained as of 1-7-1985 will attract compensation as detailed in para. 5(v).

10(iii) Application for extension shall be filed within one month of the relevant period

10(iv) Exporters to whom export entitlements are allotted in terms of this policy but who do not utilise them would render themselves liable to disqualification from future allotment without prejudice to any action that may be taken in this behalf.

11. Appeal against forfeiture of EMDs|Bank Guarantees.

For the purpose of giving consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMDs|Bank guarantee; for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMDs|Bank Guarantees by the TEXPROCIL, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will lie with Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

12. Supervision of allocation of export entitlements.

The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlement. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

13. Clearance by Customs

A. Products under restraint : Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after certifying the certification of export entitlement of the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. Handloom products : In so far as exports of all handloom fabrics|made-ups, corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in Part-2 of the combination form.

C. Made-ups falling under India Items : In respect of 'India items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden and Canada on the basis of appropriate certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

14(A) Export Certificate, Certificate of origin and Visa : The following certification required under the relevant Bilateral Textile Agreements will be issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf:—

- (i) EEC : (a) Export Certificate and Certificate of origin for all restrained items of powerloom|millmade|knitted origin.
- (b) Certificate of origin for non-restrained items of powerloom|millmade|knitted origin.
- (ii) AUSTRIA : Export certificates for fabrics|made-ups of powerloom|millmade origin subject to restraint or surveillance
- (iii) CANADA : Export certificate for fabrics and made-ups of millmade|powerloom|knitted origin which are subject to restraint except for consignments valued at less than Canadian \$ 500.
- (iv) (a) Visa for all millmade|powerloom fabrics and made-ups consignments valued US \$ 250.
- (b) Exempt certificate for consignments valued at US \$ 250 or less.
- (v) SWEDEN : Export certificate for all made-ups of millmade powerloom|handloom|knitted|crocheted origin under quantitative restraint.

14(B) Handloom exempt certificate : In the case of export of all handloom fabrics| made-up corresponding to restrained items to Canada, Cotton Handloom Textile Fabrics|Made-ups to Austria, all handloom and fabrics and made-ups to EEC and the USA the Textiles Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

15. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

16. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textiles Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows:—

1. Office of the Textile Commissioner,
New C.G.O. Building,
New Marine Lines,
Post Box No. 11500,
Bombay-400020.
2. The Cotton Textiles Export Promotion Council,
Engineering Centre,
5th Floor,
9-Mathew Road,
Bombay-400004.
3. Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council,
Resham Bhavan,
Veer Nariman Road,
Bombay-400020.

4. The Wool and Wollen Export Promotion Council.
612/714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

5. Carpet Export Promotion Council,
Shop No. B-115, Sector-XVIII,
Post Office Noida,
Distt. Ghaziabad.

6. Development Commissioner (Handicrafts),
West Block, VII, R. K. Puram,
New Delhi-110022.

7. Textiles Committee,
"Crystal", 79, Dr. Annie Besant Road,
Worli,
Bombay-400018.

P. C. JAIN, Chief Controller, Imports and Exports.